प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 7 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 7 – 14 फरवरी 2022 मूल्य पांच रूपए

आपको प्रमाणित करना होगा कि आप संपत्ति के मालिक हैं

- सरकार के प्रस्तावित लैण्ड टाइटल एक्ट से ऊभरी आशंका
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भू अधिग्रहण प्रक्रिया सरल करने के लिये लाया जा रहा है यह एक्ट
- विवाद की स्थिति में अदालत नहीं ट्रिब्यूनल में जाना होगा
- वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन है योजना

लैण्ड टाइटल एक्ट के परिदृश्य में

शिमला/शैल। मोदी सरकार अब लैण्ड टाइटल एक्ट लाने जा रही है। नीति आयोग ने इस प्रस्तावित एक्ट का ड्राफ्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र ने यह ड्राफ्ट राज्य सरकारों को भेजकर इस पर उनकी आपतियां और सुझाव आमंत्रित किये हैं क्योंकि लैण्ड राज्यों का विषय है। यदि राज्य सरकार तय समय सीमा के भीतर अपनी प्रतिक्रियायें केंद्र को नहीं भेजती हैं तो इसे उनकी सहमति मान लिया जायेगा। इसके बाद केंद्र कृषि कानूनों की तर्ज पर एक अध्यादेश जारी करके इसे लागू कर देगा। कुछ राज्यों की सहमति आने के बाद केंद्र इसे संसद में पारित करवा लेगा। राज्य सरकारों के पास नीति आयोग का ड्राफ्ट आ चुका है। हिमाचल सरकार को भी 68 धाराओं वाले इस एक्ट का ड्राफ्ट तीन सौ अनुलगकों के साथ मिल चुका है। लेकिन हिमाचल सरकार ने इसे जनता की जानकारी में नहीं लाया है। जनता से उसकी प्रतिक्रियाएं नहीं मांगी गयी हैं। 'वन नेंशन वन रजिस्टेशन' के नाम पर यह एक्ट लाया जा रहा है। माना जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में जिस तरह से व्यक्ति को अपनी नागरिकता प्रमाणित करने की वस्तु स्थिति पैदा हो गयी थी उसी तरह व्यक्ति को अपनी अचल संपत्ति का स्वामित्व प्रमाणित करने की स्थिति आ जायेगी।

इस एक्ट के आने से नीति आयोग के ड्राफ्ट के मुताबिक इससे राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल जायेगा **will provide state governments power to order for establishment, administration and management of a system of title registration of immovable properties.** नीति आयोग के मुताबिक यह एक्ट आने से इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण और उसमें मुआवजा देने की प्रतिक्रिया सरल हो जायेगी। इस समय राज्य सरकार राष्ट्रीय उच्च मार्ग, ट्रेन रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, विद्युत उत्पादन और संचारण ऑयल और गैस पाइपलाइन टेलीकॉम खनिज व खाने आदि को निजी क्षेत्र को देने की योजना बना चुकी है। निजी क्षेत्र को इसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भूमि चाहिये। इस भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया यह एक्ट आने से सरल हो जायेगी। क्योंकि इसमें आने वाले विवाद का निपटारा करने के लिए कानूनी व्यवस्था भी बदल दी गयी है।

एक्ट में यह दावा किया गया है कि **Act to provide for the establishment, administration and management of a system of conclusive property titles with title guarantee and indemnification against losses due to inaccuracies in property titles, through registration of immovable properties and further to amend the relevant Acts as stated in the Schedule.** इस दावे में जिन कमियों का कवर लिया जा रहा है वैसी ही गलतियां आगे नहीं होंगी ऐसा दावा कैसे किया जा सकता है। क्या नाम लिखाने में उच्चारण के कारण गलती नहीं हो सकती। इस समय सरकार यह दावा कर रही है कि 90 प्रतिशत गांव में अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। 655959 चिन्हित गांव में से 591221 गांव का रिकॉर्ड कंप्यूटर पर ला दिया गया है। क्या इसमें नाम आदि लिखने में गलती नहीं हुई होगी। नये एक्ट में तो राजस्व से संबंधित दस्तावेज पहले देखे ही नहीं जायेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक आईडी नंबर दे दिया जायेगा। इसमें हुई गलती को ठीक करवाने की जिम्मेदारी संपत्ति के मालिक की होगी। उसके लिए उसे संबंधित कार्यालयों के चक्कर काटने की मजबूरी हो जायेगी। सरकार यह व्यवस्था इसलिये ला रही है क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूके में ऐसा है। क्या यह व्यवस्था लाने के लिए संसद और आम आदमी के साथ एक विस्तृत बहस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। क्योंकि इसमें हर गांव और संपत्ति मालिक प्रभावित होगा। यदि सीधे नीति आयोग के ड्राफ्ट को एक्ट की शक्ल दे दी गयी तो एक बार फिर नागरिकता आंदोलन जैसे हालात पैदा होने की स्थिति बन जायेगी।

किसके नेतृत्व में लड़ेगी प्रदेश कांग्रेस अगला चुनाव उठने लगा है सवाल

शिमला/शैल। क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बदलाव होगा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के होने वाले मुख्यमन्त्री के नाम की घोषणा कर दी जायेगी? यदि ऐसी घोषणा हो जाती है तो वह चेहरा कौन होगा? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो एक कांग्रेस कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के आम आदमी के सामने आने लग पड़े हैं। क्योंकि इसी वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। भाजपा से सत्ता छीनने का सवाल होगा और इसमें यह हर समय सामने रहेगा कि संसाधनों के नाम पर कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर पायेगी। क्योंकि केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं। फिर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जेपी नड्डा से लेकर दर्जनों केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में आयेंगे। कांग्रेस को भाजपा के एक व्यवहारिक पक्ष को सामने रखकर अपनी तैयारियां करनी होगी। इसलिये यह सवाल अहम हो जाता है कि प्रदेश कांग्रेस का आकलन इस परिदृश्य में किया जाये। क्योंकि भाजपा का आकलन उस पर लगे आरोपों के आईने में कांग्रेस का उसकी आक्रमकता के आईने में किया जायेगा।

स्मरणीय है कि 2017 के चुनाव के समय स्व. वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। कांग्रेस चुनाव हार गयी थी। इस हार के बाद जब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने की बात आयी तब हाईकमान ने यह जिम्मेदारी न तो स्व. वीरभद्र सिंह को दी और न ही सुक्खू को। यह जिम्मेदारी मुकेश अग्निहोत्री को दी गयी। जबकि शायद 17 लोगों ने स्व. वीरभद्र सिंह के पक्ष में हस्ताक्षर करके उन्हें यह जिम्मेदारी दिये जाने की मांग की थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुक्खू को हटाकर कुलदीप राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी 2019 में लोकसभा की चारों सीटें हार गयी। सोलन में राजेंद्र राणा और पालमपुर में मुकेश अग्निहोत्री के हाथों में कमान थी। नगर निगम के बाद अब तीन विधानसभा और एक लोकसभा उपचुनाव पार्टी जीत गयी। मंडी लोकसभा की जिम्मेदारी फिर मुकेश अग्निहोत्री के पास थी। जिन्होंने 17 विधानसभा क्षेत्रों का संचालन किया।

इस परिपेक्ष में यह सवाल उठता है कि इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की कार्यशैली विधानसभा के भीतर और बाहर क्या रही। विधानसभा के भीतर

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने पारम्परिक स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल संकुल विश्वविद्यालय, मंडी के शिक्षण संकाय और विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि

विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारी पारंपरिक स्वास्थ्य और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि समाज वास्तविक रूप से लाभान्वित हो।

राज्यपाल ने कहा कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को जमीनी कार्यो से जोड़ना होगा, जिसके लिए विद्यार्थियों को नियमित रूप से क्षेत्रों का भ्रमण करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैव विविधता में समृद्ध है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस जैव विविधता को ग्रामीणों और शोधार्थियों की सहायता से सही रूप से प्रलेखित किया जाए, क्योंकि ग्रामीणों को स्थानीय पौधों की प्रजातियों का बेहतर ज्ञान होता है।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में राज्यपाल ने कृषि और मधुमक्खी पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों में अनुसंधान कार्य पर विशेष बल देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पास इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए समुचित अवसर हैं क्योंकि विश्वविद्यालय ने हाल ही में कार्य करना शुरू किया है। उन्होंने हर्बल गार्डन, विस्तार गतिविधियों इत्यादि को बढ़ावा देने, पारंपरिक ज्ञान को महत्व प्रदान करने और विश्वविद्यालय को इसे अपनी कार्यसूची में शामिल कर इस पर कार्य करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने पर्यावरण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर चर्चा की और इस दिशा में और अधिक शोध कार्य करने को कहा।

उन्होंने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है तथा ऐसे में हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को नशे जैसी बुराइयों से बचाने के लिए और अधिक सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की अपील की।

इस अवसर पर कुलपति प्रो. सी. एल. चंदन ने राज्यपाल का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया और विश्वास जताया कि उनका दौरा विश्वविद्यालय के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। उन्होंने राज्यपाल को विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि के बारे में अवगत करवाया और कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि कुलाधिपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने राज्य में भूस्खलन का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर संजय नारंग ने प्रस्तुति के माध्यम से विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का विवरण दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने राज्यपाल के साथ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा और गतिविधियों के संबंध में अपने अनुभव भी साझा किए।

राज्यपाल ने पारम्परिक औषधीय उत्पादों के संरक्षण एवं शोध की आवश्यकता पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मण्डी जिले के जोगिन्द्रनगर स्थित भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान का दौरा किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस केंद्र में आधुनिक तकनीक के आधार पर पारंपरिक औषधीय पौधों को उपयोगी बनाया जा रहा है। औषधीय उत्पादों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया जा रहा है और हमारे पारंपरिक उत्पादों को संरक्षित करने के लिए उन पर शोध चल रहा है। उन्होंने इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल ने औषधीय जांच प्रयोगशाला, हर्बल गार्डन एवं हर्बेरियम का भी दौरा किया।

उन्होंने परिसर में कपूर का पौधा भी लगाया।

इस अवसर पर परियोजना

अधिकारी एवं सह प्रभारी, भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान (आरआईआईएसओएम) उज्जवल दीप शर्मा ने संस्थान की गतिविधियों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हर्बल गार्डन और प्रमुख औषधीय पौधों के विकास के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाये जाने वाले हरड़, मलकांगनी, चंदन, नीम आदि औषधीय पौधों से संबंधित जानकारी भी दी और कहा कि इन पौधों की देश में अधिक मांग है।

आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अरुण चंदन ने भी औषधीय पादप बोर्ड के बारे में जानकारी दी।

औषधीय जांच प्रयोगशाला के प्रभारी विपिन शर्मा ने भी प्रस्तुति के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

स्थानीय विधायक प्रकाश राणा, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री तथा संस्थान के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इसके उपरान्त, राज्यपाल ने जोगिन्द्रनगर में सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय का भी दौरा किया।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब राज्य में मतदान के लिए विशेष सार्वजनिक अवकाश

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत या सेवाएं प्रदान कर रहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब राज्य के पंजीकृत मतदाताओं को इन राज्यों में विधानसभा के सामान्य चुनाव के दृष्टिगत मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य चुनाव के दृष्टिगत 10, 14, 20, 23, व 27 फरवरी, 3 मार्च तथा 7 मार्च, 2022 को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।

उत्तराखण्ड में 14 फरवरी तथा पंजाब में 20 फरवरी, 2022 को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य चुनाव के दृष्टिगत मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।

यह हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए मान्य होगा, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं। ये अवकाश दिहाड़ीदार कर्मचारियों तथा नेगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत सवैतनिक अवकाश होगा। प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर हिमाचल के विभिन्न भागों में कार्यरत उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का अधिकार वाले कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किया जा सकता है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करें

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने इन प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों में विशेष जागरूकता अभियान आरम्भ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में आम जनता विशेष रूप से युवाओं को शिक्षित करने के लिए एन.सी.सी. और एन.एस.एस. कैडेटों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इस संवेदनशील विषय पर पुलिस अधीक्षक, यातायात, पर्यटक एवं रेलवे पुलिस (टीटीआर) संदीप धवल ने राजभवन में राज्यपाल को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री ने जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अरूणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी हिमस्खलन की चपेट में आने से प्रदेश के दो जवानों के शहीद होने पर शोक व्यक्त किया है। इस घटना में बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र के जवान अंकेश भारद्वाज और कांगड़ा जिला के बैजनाथ क्षेत्र के राकेश सिंह सहित भारतीय सेना के सात जवान शहीद हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोकग्रस्त परिवारों को सम्बल प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि दुःख की इस घड़ी में समस्त प्रदेशवासी वीरभूमि के शहीद अंकेश और राकेश के परिवारजनों के साथ हैं।

ग्रीन टैक्स एकत्रित करने के लिए मनाली में एन.ई.टी.सी. फास्टैग बैरियर स्थापित

शिमला/शैल। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने ग्रीन टैक्स एकत्रित करने के लिए एन.ई.टी.सी. फास्टैग बैरियर स्थापित किया है। यह बैरियर मनाली के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है, जहां प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। मनाली पहुंचने वाले पर्यटक अब स्वचालित फास्टैग बैरियर पर ग्रीन टैक्स का भुगतान कर सकेंगे।

कुल्लू जिला प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आई.डी.एफ.सी. बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एन.पी.सी.आई.) के सहयोग से स्थापित अपनी तरह के इस पहले ग्रीन टैक्स बैरियर से न केवल राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि राजस्व हानि को भी रोका जा सकेगा।

मनाली आने वाले पर्यटक अब आलू ग्राउंड बैरियर पर फास्टैग के माध्यम से बिना किसी परेशानी के अपने ग्रीन टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। कुल्लू पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रबंधित, यह पहल एन.ई.टी.सी. फास्टैग के माध्यम से ग्रीन टैक्स के संग्रह में दक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बैरियर के माध्यम से पर्यटकों को गाड़ियों की लंबी कतारों से राहत मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी।

मनाली में शुरू हुए इस बैरियर से भारत सरकार के लैस कैश अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह पहल हिमाचल प्रदेश में डिजिटल लेनदेन और भुगतान को बढ़ावा देगी।

मुख्यमंत्री ने चौपाल के कुपवी खण्ड के लिए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ओक ओवर, शिमला से चौपाल क्षेत्र के कुपवी खण्ड के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भेंट की गई एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह एम्बुलेंस बैंक द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत इस दूर-दराज के क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला के माध्यम से भेंट की गई।

मुख्यमंत्री ने बैंक के प्रबंधन के इस परोपकारी कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस एम्बुलेंस से कुपवी क्षेत्र के 16,000 से अधिक निवासी लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला डॉ. सुरेखा और बैंक के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

गौण खनिज और खनिज नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों व सुरक्षा दिवारों के

निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यो के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20 हजार मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियन्ता, जोकि सहायक अभियन्ता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज़ होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फार्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर रॉयल्टी और रॉयल्टी के 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करना होगा।

बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कर्फ्यू हटाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य समारोहों, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल हैं, में 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई।

जल्द लागू होगी कांगड़ा बैंक की ओटीएस स्कीमःसुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन, संसदीय मामले, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के धर्मशाला स्थित मुख्यालय में बैंक अधिकारियों तथा निदेशक मंडल

के सदस्यों के साथ बैठक की।

सुरेश भारद्वाज ने बैंक अधिकारियों को ओटीएस पॉलिसी जल्द लागू कर एनपीए की रिकवरी को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक प्रबंधन को डिजिटाइजेशन पर जोर देते हुए मौजूदा कर्मचारियों से बढ़िया काम लेने की आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पुराना कांगड़ा बैंक सिर्फ कांगड़ा ही नही अपितु पूरे प्रदेश की शान है और इस ऐतिहासिक संस्था को अगले 100 वर्षो के लिए और अधिक सशक्त करने के लिए ना सिर्फ बैंक प्रबंधन से आने वाले प्रस्तावों पर यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी बल्कि सरकार के स्तर पर भी बैंक प्रबंधन को हर संभव मदद और सहयोग दिया जायेगा।

बैंक के प्रबंध निदेशक विनय कुमार ने सहकारिता मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें बैंक की मौजूदा हालात से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बैंक जहां हर क्षेत्र में प्रगतिशील है वहीं बढ़ता हुआ एनपीए बैंक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके समाधान के लिए बैंक द्वारा की जा रही कार्यवाही से भी सहकारिता मंत्री को अवगत करवाया गया। एनपीए रिकवरी के संदर्भ में प्रबंध निदेशक ने बताया कि एनपीए रिकवरी के लिए बैंक जल्दी ही ओटीएस पॉलिसी लागू करने जा रहा है जिससे मौजूदा वित्तीय वर्ष में बैंक एक बड़ी एनपीए रकम की रिकवरी करने में सफल होगा।

इस दौरान बैंक अधिकारियों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नाबार्ड के मौजूदा सीएमए नियमों के तहत पुराने बड़े ऋणों का नवीकरण ना होना भी बैंक के एनपीए के बढ़ने का एक मुख्य कारण है।

इस मौके पर अतिरिक्त पंजीयक सहकारी सभाएं, धर्मशाला सुखदेव सिंह, बैंक के निदेशक चंद्र भूषण नाग, राजीव महाजन, गायत्री कपूर, शेर सिंह चौहान व अन्य बैंक अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य सरकार कामगारों व श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्पः जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारतीय मजदूर संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कामगारों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में करूणामूलक आधार पर रोजगार के मामलों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को पंचायत वैटरनरी सहायकों के नियमितिकरण के मामलों पर उदारतापूर्वक विचार करने

के भी निर्देश दिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने चार वर्षो के कार्यकाल में दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी 210 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन की है, जिससे उन्हें मासिक 2700 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाले श्रमिकों को पर्याप्त और समुचित दिहाड़ी सुनिश्चित की है। सभी दिहाड़ीदारों को साप्ताहिक अवकाश भी प्रदान किया जा रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि गत चार वर्षो में प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की राशि में 1750 रुपये की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षो में राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकताओं के मानदेय में भी 2850 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है और आज उन्हें 7300 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंशकालिक राजस्व कार्यकर्ताओं और स्नातक जल कार्यकर्ता लिपिक (वाटर वर्कर क्लर्क) से सम्बन्धित मामलों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के श्रमिकों और कर्मचारियों की मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्डो और निगमों की सर्विस कमेटी की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में सीमेंट संयंत्र प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर सीमेंट संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में आंतरिक गतिविधियों के लिए ठेकेदारों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को श्रमिकों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में देश में सबसे अधिक कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और भारत तथा हिमाचल प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भारतीय मजदूर संघ ने इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों ने भी परीक्षा की इस घड़ी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष तौर पर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्यकर्ताओं ने महामारी के दौरान अपनी सराहनीय सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष के बजट में इस बैठक में प्राप्त सुझावों को शामिल करने का भी प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षकों की पदोन्नति का कोटा 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नवसृजित 412 पंचायतों में पंचायत चौकीदारों के पदों को सृजित करने और भरने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के अध्यक्ष मदन राणा ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा ही कर्मचारियों और श्रमिकों की विभिन्न मांगों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट तैयार करते समय मजदूरों और मजदूर वर्ग की विभिन्न मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि भारतीय मजदूर संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता राज्य सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करेगा।

श्रम आयुक्त आशीष सिंघमार ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार आर.डी. धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा, आर.डी. नजीम और देवेश कुमार, सचिव डॉ. अजय शर्मा, विकास लाबरू, राजीव शर्मा, अमिताभ अवस्थी और राकेश कंवर, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, बीएमएस के महासचिव यशपाल हेट्टा सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती योजना आरम्भ

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों और विभागीय अधिकारियों के अनुरोध पर माल और सेवा कर में सम्मिलित अधिनियमों के तहत लम्बित मामलों और बकाया राशि के निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती योजना (विरासत मामले समाधान) 2021 आरम्भ की गई है। इससे करदाताओं को अनिवार्य दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जीएसटी लागू होने के बाद भी करदाताओं के कर संबंधी मामलों के विवाद रह गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत, डीलर योजना के पहले चरण के दौरान ब्याज और जुर्माने के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से निपटान शुल्क के साथ अपना देय कर जमा कर सकते हैं, जिसकी अवधि 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त होगी। पहले चरण के दौरान आवेदन दाखिल करने में विफल रहने वाले डीलरों को निपटान शुल्क का भुगतान करना होगा अर्थात पहले चरण के दौरान लागू देय निपटान शुल्क का 150 प्रतिशत, दूसरे चरण की अवधि 29 अप्रैल से 28 जून, 2022 तक लागू होगी। योजना के तहत, करदाता बकाया कर राशि का भुगतान कर सकते हैं और कानून के तहत किसी भी अन्य परिणाम से मुक्त हो सकते हैं। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और उन्हें ब्याज व जुर्माने के स्थान पर केवल निपटान शुल्क देना होगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र डीलरों को अपने नजदीकी जिला/वृत्त कार्यालय में जाना होगा। उन्होंने डीलरों को योजना के समाप्त होने से पहले इस अवसर का लाभ उठाने का परामर्श दिया।

उद्योग विभाग द्वारा 70 करोड़ के निवेश वाली 33 इकाइयां स्वीकृत

शिमला/शैल। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने बताया कि विभाग की राज्य स्तरीय समिति की आठवीं बैठक में 33 नये मामलों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें 11 औद्योगिक एवं 22 पर्यटन इकाइयां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ के निवेश वाली इन इकाइयों को विभाग द्वारा 20.25 करोड़ रुपये का उपदान प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से राज्य के 755 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय समिति की पिछली सात बैठकों में 168.65 करोड़ रुपये के 118 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस औद्योगिक विकास योजना में केन्द्रीय पूंजी, ऋण प्राप्ति के लिए निवेश प्रोत्साहन (सी.सी.आई.आई.ए.सी.) 30 प्रतिशत की दर पर तथा निवेश संयंत्र और मशीनरी में पांच करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक के निवेश वाली इकाइयां शामिल है। योजना के तहत सभी पात्र औद्योगिक इकाइयां तथा मौजूदा इकाइयां शत-प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी।

ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

बैंक फ्राड के माध्यम से लूट कब तक

बैंकों में फ्राड के माध्यम से आम आदमी के पैसे की लूट कब तक जारी रहेगी? जो प्रधानमंत्री यह कहते थे ''ना खाऊंगा न खाने दूंगा'' वह इस लूट पर चुप क्यों है? क्या प्रधानमंत्री ने चौकीदार की भूमिका छोड़ दी है या इस पर अपनी मौन सहमति दे रखी है? इस तरह के कई सवाल गुजरात स्थित एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा 22842 करोड़ का बैंक फ्राड सामने आने के बाद उठ खड़े हुये हैं। क्योंकि इस कंपनी ने यह फ्राड 2012 से 2017 के बीच में किया है। 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर यह फ्राड पहला फ्राड नहीं है बल्कि पहले पिछले 7 वर्षो में करीब 6 लाख करोड़ के बैंक फ्राड हो चुके हैं और अभी तक एक भी गुनाहगार पकड़ा नहीं गया है। इस फ्राड के सामने आने के साथ ही इस दौरान बैंकों के 25.24 लाख करोड़ के एनपीए में से 7 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया जाना भी चर्चा में आ गया है। करीब 13 लाख करोड़ का धन बैंक फ्राड और एनपीए के राइट ऑफ किये जाने से नष्ट हो गया है। जबकि इस वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में सरकार की कुल आय ही 23 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इस आय में भी 65 हजार करोड़ सरकारी संपत्तियों के विनिवेश से जुटाया जायेगा। ऐसे में जिस भी व्यक्ति को सरकार के वित्तीय प्रबंधन की यह जानकारियां रहेगी उनके लिये यह सारे मुद्दों से बड़ा सवाल होगा। क्योंकि इसके कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी जिसका सब पर असर पड़ेगा।

आज यदि 2014 की तुलना में महंगाई और बेरोजगारी का आकलन किया जाये तो इसमें 100 प्रतिशत से भी ज्यादा की बढ़ौतरी हुई है और इसी अनुपात में देश की 80 प्रतिशत से अधिक की जनता के आय के साधन नहीं बढ़े हैं। बल्कि इस दौरान बैंकों में जमा आम आदमी के जमा पर ब्याज दर कम हुई है। यही नहीं जीरो बैलेंस के नाम पर खोले गये बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस 1000 और डाकघरों में 500 रखने की शर्त लागू है। इस न्यूनतम पर खाता धारक को कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि बैंकों को इससे कमाई हो रही है। इस संदर्भ में यह कहना ज्यादा सही होगा कि सरकार इन लुटेरों की लूट की भरपाई आम आदमी की जेब पर अपरोक्ष में डाका डाल कर रही है। इस लूट और डाके पर हिंदू – मुस्लिम मंदिर – मस्जिद हिजाब और धारा 370 तथा तीन तलाक के मुद्दे खड़े करके बहस को लंबित किया जा रहा है। लेकिन यह तय है कि देर सवेर महंगाई और बेरोजगारी जब बर्दाश्त से बाहर हो जायेंगी तब जो रोष का सैलाब आयेगा वह सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जायेगा। क्योंकि जब बैंकों का एनपीए सरकार की राजस्व आय से बढ़ जाता है तो उस बैंकिंग व्यवस्था को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। यह सरकार इस लूट के लाभार्थियों पर हाथ डालने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने क्रिप्टो को अभी तक लीगल करार नहीं दिया है लेकिन इससे हुई कमाई पर टैक्स लेने की घोषणा बजट में कर रखी है। यह अपने में स्वत: विरोध है और इसी तरह के विरोधों पर यह सरकार टिकी हुई है। अब नीति आयोग सीधे नीति बनाकर सरकार को दे रहा है। नीति निर्धारण में संसद की भूमिका नहीं के बराबर रह गई है।

इस परिदृश्य में यह सवाल और भी अहम हो गया है कि प्रधानमंत्री इस सब पर चुप क्यों है? क्या सत्तारूढ़ भाजपा को इस लूट में हिस्सा मिल रहा है? यह हिस्से की चर्चा इसलिये उठ रही है क्योंकि इस समय भाजपा की घोषित संपत्ति वर्ष 2019 – 20 के लिए 4847 .78 करोड़ दिखाई गई है। यह संपत्ति कार्यकर्ताओं के चंदे से संभव नहीं है। तय है कि इसके लिये बड़े घरानों से चुनावी बॉडस के माध्यम से बड़ा चंदा आया है और यह बॉडस गोपनीयता के दायरे में आते हैं इसलिए सार्वजनिक नहीं हो रहे। इसी कारण से लूट पर चुप्पी साधनी पड़ रही है। लेकिन इन चुनावों में जिस तरह से किसान समुदाय ने भाजपा का विरोध किया है उसमें आने वाले दिनों में जब महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित आम आदमी भी शामिल हो जायेगा तो एकदम स्थितियां बदल जायेंगी यह तय है।

अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी भारत ने 'कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप' का शुभारंभ किया

शिमला। अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), भारत के सहयोग से 'विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप (सीआईएफ) का शुभारंभ किया।

इस फेलोशिप को 'प्री – इनक्यूबेशन मॉडल' के रूप में विकसित किया गया है जो युवाओं को सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सामाजिक उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी।

यह एक साल की अवधि तक चलने वाला गहन फेलोशिप कार्यक्रम होगा, जिसे सामाजिक – आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना महत्वाकांक्षी सामुदाय नवप्रवर्तक के लिए तैयार किया गया है। इस फेलोशिप की अवधि के दौरान, प्रत्येक फेलो को अटल नवाचार मिशन के किसी अटल समुदाय नवाचार केंद्र से संबद्ध किया जाएगा। जो अपने आइडिया पर काम करते हुए एसडीजी जागरूकता, उद्यमशीलता कौशल और जीवन कौशल प्राप्त करेगा। एसीआईसी नव प्रवर्तक को परिचालन सुविधाओं, सह – कार्यस्थलों, प्रयोगशालाओं और गतिशील व्यापार नेटवर्क के रूप में उचित संसाधन प्रदान करके युवा नेतृत्व वाले नवाचारों से पोषित करेगा।

एसीआईसी के माध्यम से यह फेलोशिप नवप्रवर्तक की यात्रा को एक वर्षीय केंद्रित मॉडल के माध्यम से उसके आइडिया से लेकर व्यावसायीकरण तक ले जाएगी। यह कार्यक्रम महत्वाकांक्षी सामुदायिक नवप्रवर्तकों के बीच ज्ञान और क्षमता निर्माण की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करेगा जो उनकी उद्यमिता के लिए आवश्यक है। यह एक तरीका है जिसके साथ एआईएम स्टार्ट – अप इको – सिस्टम में एक संस्कृति के साथ – साथ देश में विभिन्न भागों से महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की संस्कृति के रूप में सामाजिक उद्यम को मुख्य धारा में लाने के लिए युवाओं की भागीदारी हासिल करने का प्रयास करेगा।

फेलोशिप के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि यह फेलोशिप एक साल तक चलने वाला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य युवा समुदाय के नवप्रवर्तकों को उनकी उद्यमशीलता यात्रा में आवश्यक बुनियादी ढांचा और ज्ञान प्रदान करना है। यह रचनात्मकता और भारत के जमीनी स्तर पर मौजूद नवाचारी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक प्रेरक पहल है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस फेलोशिप को अधिक सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर आना चाहिए क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक लगन और उत्साह की आवश्यकता होगी।

इस फेलोशिप के शुभारंभ के अवसर पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि युवा और ऊर्जावान नवप्रवर्तकों के लिए प्री – इनक्यूबेशन जगह बनाना सामुदायिक समस्याओं के लिए जीवंत और प्रेरक समाधान हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह फेलोशिप समग्र और समावेशी नवाचारों के निर्माण में युवा परिवर्तनकर्ताओं के साथ – साथ सामुदायिक नवाचार इको – सिस्टम में अन्य हितधारकों को शामिल करने का एक बेहतर तरीका है।

इस फेलोशिप के माध्यम से नवाचारी इको – सिस्टम में विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए भारत में यूएनडीपी के स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा ने कहा कि इस फेलोशिप पहल के माध्यम से हम युवाओं को स्वयं अपने समाधान खोजने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वे ऐसे उद्यम बना सकें जो सतत व्यवसाय मॉडल हों। एआईएम और यूएनडीपी यह काम करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्री – इनक्यूबेशन मॉडल की जरूरत पर जोर देते हुए मिशन निदेशक, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग डा. चिंतन वैष्णव ने कहा कि यह देश के छोटे शहरों और गांवों में सामुदायिक केंद्रित नवाचार में मदद कर सकता है। यह फेलोशिप सभी तत्वों – मूल्यों, उपायों और हितधारकों का एक समावेश है जो एक स्थायी सामुदायिक नवाचार इको – सिस्टम के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। युवा नवोन्मेषकों को इस फेलोशिप के माध्यम से सीखने, समुदाय और राष्ट्र में बड़े पैमाने पर प्रभाव पैदा करने का बड़ा अवसर उपलब्ध हो रहा है।

उन्होंने कहा कि समुदाय के लिए, समुदाय के साथ और समुदाय में नवाचार लाने के उद्देश्य से यह फेलोशिप और परिचालन मैनुअल से सतत विकास लक्ष्यों (एसजीडी) को लक्षित करके समुदायों में स्थायी परिवर्तन के लिए नए समाधान करने और उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरणा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, एआईएम ने एसीआईसी इको – सिस्टम की स्थापना के लिए परिचालन नियमावली भी जारी की है। मैनुअल एक ज्ञान और क्षमता निर्माण ढांचा है, जो एक एसीआईसी के मूलभूत और परिचालन कामकाज में मदद करेगा। यह मैनुअल उन स्तंभों के निर्माण पर आधारित है जो एक समग्र नवाचार इको – सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य के लिए एक सहायक प्रणाली को तैयार करने और उसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एसीआईसी की स्थापना देश के कम विकसित क्षेत्रों में स्टार्ट – अप और नवाचार इको – सिस्टम को विकसित करने पर ध्यान देने के साथ की गई है। वर्तमान में, देश के 9 राज्यों में 12 एसीआईसी हैं और देश में ऐसे 50 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लोगों द्वारा बंजर भूमि पर 250 किलोवाट से 1 मैगावाट तक ग्रिड कनेक्टिड सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाये जा रहे

शिमला। हिमऊर्जा ने पीएम – कुसुम (प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) के अर्न्तगत घटक 'क' में लोगों द्वारा बंजर भूमि पर 250 किलोवाट से 1 मैगावाट तक ग्रिड कनेक्टिड सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं, जिससे न केवल लोगों को रोज़गार के अवसर मिले हैं, बल्कि बंजर पड़ी भूमि को भी उपयोग में लाया गया है और लोगों की आय में वृद्धि हुई है। इस योजना पर काम जारी है।

हिमऊर्जा शिमला के डीपीआरओ पन्नालाल शर्मा ने पीआईबी को बताया कि हिमऊर्जा द्वारा कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल के प्रत्येक घरों में 250 – 250 वॉट के ऑफ ग्रिड पावर प्लांट लग रहे है। पांगी उपमंडल के सभी 2162 बी.पी.एल. परिवारों के लिए 250 – 250 वॉट के (प्रत्येक)घर में ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट निशुल्क प्रदान किए गए हैं। इसी तरह कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र के सभी 168 घरों में ऑफ ग्रिड पावर प्लांट निशुल्क स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में 'करेरी' (4.80 MW) जल विद्युत परियोजना जिला शिमला के रामपुर के समीप स्थापित की गयी है।

केंद्रीय बजट 2022–23 के मायने

– वी. अनंत नागेश्वरन –

वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत 2022-23 के बजट की 4 प्रमुख विशेषताएं (4 सी) हैं - निरंतरता, यथार्थता, पारंपरिक व्यापार बुद्धिमत्ता और बड़ी परियोजना के साथ छोटी परियोजनाओं की शुरुआत।

बजट ने दो साल पहले शुरू की गई प्रथा, जिसके तहत सभी व्यय को कारोबार की आय के साथ रखा जाता है, को जारी रखा है। अतिरिक्त-बजटीय संसाधन(जिनमें उधार की गारंटी और इसकी प्रक्रिया, केंद्र सरकार के द्वारा पूरी की जाती है(चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों (आरई) में 750 करोड़ रुपये के एकल परिवर्तनीय मद तक सीमित रखा गया है। बजट को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता और त्रुटिहीन लेखांकन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है, जैसा पिछले दो बजटों में भी देखा गया है।

पिछले दो वर्षों में, वैश्विक महामारी की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा आपातकालीन ऋण योजनाओं तथा आपातकालीन खाद्यान्न समर्थन (पीएम गरीब कल्याण योजना) के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान की गयी है। इनमें सार्वजनिक वितरण की पात्रता के साथ-साथ अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन, जिसे कई बार विस्तार दिया गया है तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम व पीएम-किसान के आवंटन में वृद्धि शामिल हैं।

इस वर्ष के बजट में, आपसी-संपर्क आधारित क्षेत्रों, जो अभी तक अपने महामारी-पूर्व के स्तर पर वापस नहीं आ पाए हैं, के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना का विस्तार किया गया है। सूक्ष्म एवं माध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट में सुधार और इसमें अतिरिक्त पूंजी के आवंटन से एमएसएमई को 2.0 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा मिलेगी।

सरकार ने अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत की है और इसके लिए महामारी आपदा का उपयोग एक अवसर के रूप में किया गया है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं - 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, पूर्वव्यापी कराधान से जुड़ी अनिश्चितता को समाप्त करना, निजीकरण, करदाता की उपस्थिति या सम्बंधित जानकारी के बिना (फेसलेस) आयकर मूल्यांकन और कॉर्पोरेट एवं व्यक्तिगत आयकरों में कमी, जहाँ करदाता कम या बिना छूट के कर के निम्न दर का विकल्प चुन सकते हैं या पुरानी पद्धति के तहत रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण प्रक्रिया-आधारित उपायों, जैसे गति शक्ति डैशबोर्ड का शुभारंभ, सरकारी खरीद में सुधार, फैक्टरिंग कानूनों में बदलाव और खाता संगणक (एग्रीगेटर) रूपरेखा की शुरुआत की गयी है।

2022-23 का बजट, संरचनात्मक सुधारों और प्रक्रिया-सुधार के संयोजन से जुड़े दृष्टिकोण पर आधारित है। गति शक्ति के तहत विभिन्न पहल, एमएसएमई को ऋण सुविधाओं की सहायता देने के लिए कई पोर्टलों (उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम) को आपस में जोड़ना, कौशल और क्षमता-वृद्धि, डाकघरों को कोर-बैंकिंग समाधान के साथ सक्षम बनाना, आयकर प्रपत्र में पिछले दो साल तक की त्रुटियों को ठीक करने के लिए वर्तमान के आयकर प्रपत्र में उल्लेख की सुविधा और चयनित क्षेत्रों के अंतर्गत विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना के लिए गिफ्ट शहर में सुविधा उपलब्ध कराना आदि को कुछ उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है।

मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर का पूर्वानुमान कई लोगों को बहुत अधिक रूढ़िवादी लग सकता है, खासकर यह देखते हुए कि आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत से लेकर 8.5 प्रतिशत के बीच की विकास दर का अनुमान लगाया गया है। चाहे कुछ भी हो, तिमाही दर तिमाही आधार पर वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी की गिरावट को देखते हुए इस पूर्वानुमानित वृद्धि दर के नीचे रह जाने के बजाय ऊपर चले जाने की संभावना अधिक है। यह वर्ष 2022-23 के लिए एक सकारात्मक आधार प्रभाव पैदा करता है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में आर्थिक गतिविधियों पर ओमिक्रोन वैरिएंट के असर की वजह से यह प्रभाव थोड़ा कमजोर रह सकता है। अगरवर्ष 2022-23 के दौरान विविध बाहरी झटके (तेल की कीमत का झटका, वैश्विक वित्तपोषण की स्थिति को प्रभावित करने वाला फेड की मौद्रिक नीति का सामान्यीकरण आदि) भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, तो 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर रूढ़िवादी लगने के बजाय विवेकपूर्ण लग सकती है।

एयर इंडिया में लगभग 52000 करोड़ रुपये के नकद प्रवाह को अलग रखने के बाद, सरकार का पूंजीगत व्यय संशोधित बजट अनुमान की तुलना में 36 प्रतिशत (और वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से 35.4 प्रतिशत) अधिक हो जाएगा। इसमें राज्य सरकारों को पूंजी प्रवाह के लिए एक लाख करोड़ रुपये का 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को (इक्विटी के रूप में प्रदान किया गया) 69000 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के 65000 करोड़ रुपये से अधिक) की वृद्धिशील बजटीय सहायता भी शामिल है। ये सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं।

अगर राज्य सरकारों को अतिरिक्त उधार सीमा के रूप में इन एक लाख करोड़ रुपये की अनुमति दी जाती, तो उन्हें एक ऐसे ब्याज दर को वहन करना पड़ता जो उस दर से अधिक है जिस पर केन्द्र सरकार उधार लेती है। इसके अलावा, इस धन का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया जा सकता है। यह ब्याज मुक्त ऋण, जोकि पूंजीगत व्यय के लिए समर्पित है, इस प्रकार के व्यय को प्रोत्साहित करता है। तथ्य यह है कि नवंबर 2021 तक राज्यों का पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष के इसी समान आठ महीनों की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक था और यह पूरी तरह से पूंजीगत व्यय उद्देश्यों के लिए 50 वर्ष के इस ब्याज मुक्त ऋण के संगत में है।

हाल के वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूंजीगत निवेश का वित्त पोषण उल्लेखनीय रूप से उधार के माध्यम से किया गया है और इससे इसके ब्याज का बोझ बढ़ गया है। सरकार बढ़ी हुई बजटीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय राजमार्गों में निरंतर निवेश सुनिश्चित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वित्तीय रूप से एक सक्षम इकाई बनाए रखने की दृष्टि से इसे मजबूत कर रही है।

जैसे ही आत्मविश्वास और उत्साह के बूते नागरिकों के दिमाग पर इस समय छाई महामारी-जनित चिंताएं दूर होंगी, बजट में घोषित किए गए विभिन्न उपाय और उसमें परिकल्पित पूंजीगत निवेश संबंधी कदम निजी निवेश का अंबार लगाने में सफल होंगे।

लेखक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं

विलुप्त होती जड़ी बूटियों की पहचान होगी आसान
वादी-ए-भूलाह में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क तैयार

शिमला। वादी-ए-भूलाह, प्रदेश के साथ-साथ देश-विदेश के शोधकर्ताओं, पर्यटकों और हिमालय की विलुप्त होती जड़ी-बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए तैयार है। जंजैहली घाटी के भूलाह में एक करोड़ की लागत से स्थापित किया गया प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क (जैव विविधता उद्यान) हिमालय की विलुप्त होती जड़ी-बूटियों के संरक्षण के साथ-साथ शोधकर्ताओं व पर्यटकों के लिए भी वरदान साबित होगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के विजन को साकार करते, राज्य के इस पहले जैव विविधता पार्क को हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज (एनएमएचएस) प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बनाया गया है। यह राज्य का पहला पार्क है जिसमें विलुप्त होती जड़ी-बूटियों को संरक्षित करने पर बल दिया गया है। पार्क को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के साथ-साथ शोधकर्ताओं के लिए हिमालय में पाई जाने वाली विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों (हर्बल प्लांट्स) पर शोध करने के नए मौके देने के लिए भी तैयार किया गया है जो विलुप्त होने के कगार पर है।

पार्क में प्रदर्शन के लिए पहाड़ों में विलुप्त हो रही जड़ी-बूटियों की हर्बल नर्सरी तैयार की गई है। इस नर्सरी में नाग छतरी, धूप, कडू, सर्पगंधा, चिरायता, टैक्स, बर्बरी, चौरा, पठानबेल, पत्थर चटा, भूतकेसी, न्यार, मुश्कवाला, वण, अजवायण, कूठ व वर्रे, संसरपाली, डोरी घास, रतन जोत, अतीश पतीश, वन ककड़ी, शिंगली मिगली, जगली लहसुन, डुंगतली, इत्यादि जड़ी बूटियां प्रदर्शित की गई है। यहां देश-विदेश का कोई भी शोधकर्ता इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपना शोध कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त हर उस जड़ी बूटी पर भी खोज कार्य किया जा सकेगी, जिनकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। इस हर्बल नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1200 पौधे शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में स्थापित गए राज्य के पहले इस अनूठे पार्क को 5 हेक्टेयर यानि 60 बीघा से अधिक भूमि पर तैयार किया गया है। यहां शोधकर्ताओं के लिए विभिन्न मूलभूत सुविधाएं भी जुटाई गई हैं। भूलाह की सुंदर वादियों में स्थापित इस पार्क को चारों ओर से बाड़बंदी कर सुरक्षित बनाया गया है। एनएमएचएस प्रोजेक्ट के विभिन्न कार्य लगभग 15 हेक्टेयर भूमि पर किए गए है।

यहां आने वाले शोधकर्ताओं व पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्क में एम्फी थियेटर भी बनाया गया है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकेगी। पार्क में देश-विदेश से आने वाले शोधकर्ताओं के लिए रहने खाने की व्यवस्था के लिए दो लॉग हट भी निर्मित किए गए है। इसके अलावा दो लॉग्स हट, वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, इंटरनल टैंक, 5 किलो वाट बिजली तैयार करने वाला प्रोजेक्ट, एम्फी थिएटर, पक्षियों के घोंसले, हर्बल नर्सरी, फूट ब्रिज व बिक्री केंद्र इत्यादि तैयार किया गया है।

पर्यटकों के लिए पार्क में दो ट्री-हट भी तैयार किए गए हैं, जहां से वे पार्क सहित अन्य रमणीक स्थलों को निहार सकते हैं। इसके अलावा लगभग 2 किमी की दूरी तक नेचर ट्रेल्स बनाई गई हैं। 25 फीट ऊंची व 160 मीटर लंबी ट्री-वॉक तैयार की गई है। इसके अलावा सात फुट ब्रिज बनाए गए हैं। पार्क के साथ लगते टैक्सस के जंगल में शोधकर्ताओं के लिए इंटरनल ट्रैक बनाया गया है, जिसमें वे आसानी से घूम कर अपना रिसर्च कार्य कर सकते हैं।

वर्तमान में देश भर में 966,363 इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर हैं

शिमला। देश में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर 2015 से इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (हाइब्रिड एवं) स्कीम (फेम इंडिया) आरंभ की। वर्तमान में फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ पहली अप्रैल, 2019 को पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:

सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों में कमी लाने के लिए देश में ही एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए 12-05-2021 को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। बैटरी की कीमतों में कमी आने का परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी के रूप में आएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत कवर किया जाता है जिसे 25,938 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ 15 सितंबर, 2021 को पांच वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दी गई।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत की गई, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत की गई।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की कि बैटरी चालित वाहनों को हरे रंग के लाइसेंस प्लेट दिए जाएंगे तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों से सड़क कर माफ करने का परामर्श देते हुए एक अधिसूचना जारी की जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की आरंभिक लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की विस्तृत सूची निम्नलिखित है:

31-01-2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों की राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	कुल योग
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	159
अरुणाचल प्रदेश	20
असम	47,947
बिहार	64,241
चंडीगढ़	1,931
छत्तीसगढ	13,428
दिल्ली	132,302
गोवा	1,686
गुजरात	17,593
हरियाणा	26,780
हिमाचल प्रदेश	711
जम्मू और कश्मीर	1,527
झारखंड	12,171
कर्नाटक	82,046
केरल	15,022
लद्दाख	5,496
महाराष्ट्र	58,815
मणिपुर	540
मेघालय	28
मिजोरम	20
नगालैंड	171
उड़ीसा	12,282
पुदुचेरी	1,614
पंजाब	10,142
राजस्थान	53,141
सिक्किम	2,425
तमिलनाडु	50,296
त्रिपुरा	7,593
केंद्र शासित प्रदेश डीएनएच और डीडी	277
उत्तर प्रदेश	276,217
उत्तराखंड	25,451
पश्चिम बंगाल	44,291
कुल योग	**966363**

17 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों को 1 फरवरी, 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से 1.30 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित होगी।

इसके अतिरिक्त 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य सेवानिवृत हुए लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और ग्रेयचुटी भी मिलेगी। अब 1 जनवरी, 2016 से न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 9000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने 1 जनवरी, 2016 से ग्रेयचुटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की, जो एन.पी.एस. कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।

राज्य के 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश सरकार के एन.पी.एस. कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिस पर 250 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने 1 जुलाई, 2021 से पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सालाना 1785 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में पहले ही 1450.44 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में 17 फरवरी, 2022 से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया। बैठक में सभी ज़िम और सिनेमा घरों को खोलने तथा सभी तरह के लंगरों के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर उप-अग्निशमन अधिकारी के आठ पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला के धीरा में, चम्बा जिला के भटियात में और मण्डी जिला के रिवालसर में तीन नए उप-अग्नि केन्द्र खोलने तथा शिमला जिले के चिड़गांव, हमीरपुर जिले के भोरंज और अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में तीन नए फायर पोस्ट खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने प्रत्येक नव सृजित उप-अग्नि केन्द्र के लिए उप-अग्निशमन अधिकारी का एक पद, लीडिंग फायरमेन के दो पद, फायरमेन के 14 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के 6 पद तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमेन का एक पद, फायरमेन के 12 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के चार पदों का सृजिन कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिद्र इन प्रत्येक उप-अग्नि केन्द्रों के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर, एक वाटर ब्राउज़र और एक कार्बनडाईऑक्साइड वाहन तथा प्रत्येक नव गठित फायर पोस्ट के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर और एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन स्वीकृत किए गए हैं।

बैठक में किन्नौर जिला में जल शक्ति मण्डल रिकॉगपिओ के तहत सांगला में जल शक्ति उप-मण्डल खोलने के अतिरिक्त कड़छम में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया गया। इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई में जल शक्ति मण्डल तथा बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा में जल शक्ति उप-मण्डल खोलने तथा इस मण्डल के तहत नए अनुभाग के सृजन और इस कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन को मंजूरी दी। बैठक में जल शक्ति मण्डल नम्बर-2 कुल्लू को कर्मचारियों सहित शमशी से लारजी स्थानातंरित करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला सोलन के चंडी में लोक निर्माण विभाग के उप-मण्डल को खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में जिला लाहौल-स्पिति के उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला मण्डी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छोलथड़ा, सजाओं तथा छोलगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया तथा इन केन्द्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणी के 16 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के बकराता दरपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस केन्द्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला लाहौल-स्पिति के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काजा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा किमो में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने त्वरित देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों को निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा-108 के तहत 50 अतिरिक्त एम्बूलेंस खरीदने तथा संचालन को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के त्रिलोकनाथ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने तथा अनुबंध आधार पर व्याख्यता के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार और मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य नई केंद्रीय प्रायोजित योजना फाइनेंसिंग फेसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना से कृषि समुदाय को बड़े पैमाने में लाभ होगा क्योंकि फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और ई-मार्केट प्लेटफॉर्म, गोदामों, सिलोज, पैक हाउस, कोल्ड चेन जैसे सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।

बैठक में मण्डी में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2022 को 1 अप्रैल, 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के जीतपुर बहेड़ी में आई.जी. इथनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन को एक रुपया प्रति वर्ग मीटर पटा दर पर भूमि आवंटित करने को अनुमति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला की तहसील नूरपुर के सदवां में उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लाहौल-स्पिति जिला की केलांग तहसील के कारगा गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोलधार, बाग चुवासी, जाच और कांदी टिक्कर को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, कुल्लू जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्योली, मेहा और शालीन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा मण्डी जिला में राजकीय उच्च विद्यालय हराबोई, काहनू, रीचानी, पालाहोटा, चम्बी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा कुल्लू जिला में राजकीय उच्च विद्यालय डोगरी, सारी, जिन्दुआर और हलान-1 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 82 पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के घण्डालवी में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया।

फिट इंडिया क्विज के प्रारंभिक दौर में हिमाचल के तीन स्कूलअव्वल

शिमला/शैल । केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जाने-माने एथलीटों के साथ 10 फरवरी से शुरू हो रहे पहले फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तरीय दौर के लिए छात्रों का उत्साहवर्धन किया है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 189 जिलों के 360 स्कूल पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

अनुराग ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि भारत की पहली स्कूल फिटनेस और स्पोर्ट्स क्विज का शुभारंभ 'फिट इंडिया क्विज' शीर्षक से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक पहल है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने का आहवान किया था। प्रश्नोत्तरी के प्रारंभिक दौर में भारत भर में भाग लेने वाले सभी छात्रों को बधाई देते हुए ठाकुर ने सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगियों को अपने स्कूल, जिले और राज्य को गौरवान्वित करने के लिए शुभकामनाएं दीं।

क्विज के प्रारंभिक दौर में 13,502 स्कूलों के कुल 36,299 छात्रों ने हिस्सा लिया और इसमें लड़कों के साथ-साथ लड़कियों ने भी समान रूप से भाग लिया। उत्तर प्रदेश के दो छात्रों ने प्रारंभिक दौर में शीर्ष अंक प्राप्त करके अन्य सभी राज्यों के छात्रों को पीछे छोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश में दून वैली पब्लिक स्कूल के जशनप्रीत सिंह ने प्रारंभिक दौर में पहला, जबकि एमआईए डीएवी पब्लिक स्कूल के अक्षत ठाकुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। टॉपर्स में तीसरा स्कूल समूर कलां सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऊना जिला से है। । इसके अलावा, सोलन, शिमला, किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू और कांगड़ा के 13 अन्य स्कूलों के छात्रों ने भी प्रारंभिक दौर में क्वालीफाई किया है।

राज्य स्तरीय दौर, एक वेब-आधारित प्रतियोगिता होगी, जिसमें 8 से 32 टीमें स्टेट चैंपियन बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस कार्यक्रम का युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रसारण (वेबकास्ट) होगा। क्विज में 3.25 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि है, जो क्विज के विभिन्न चरणों के दौरान विजेता स्कूलों और छात्रों को दी जाएगी।

राज्य स्तरीय दौर के बाद, 36 स्कूल टीमें (प्रत्येक राज्य और/या केंद्र शासित प्रदेश की विजेता) राष्ट्रीय दौर में प्रवेश करेंगी, जो इस साल के अंत में आयोजित होगी। इसे स्टार स्पोर्ट्स पर प्रसारित किया जायेगा और कई सोशल मीडिया चैनलों पर भी इसका प्रसारण (वेबकास्ट) होगा।

ठाकुर के साथ बहुत से जाने-माने एथलीटों ने भी भाग लेने वाले छात्रों को आगामी दौर के लिए शुभकामनाएं दी हैं। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने कहा, ''मैं प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देती हूं।'' टोक्यो पैरालिंपिक कांस्य पदक विजेता शरद कुमार ने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और सभी अपने राज्य को पहली बार फिट इंडिया क्विज का चैंपियन बनने के लिए उत्साहित करेंगे।' टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने कहा, 'मैं प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देती हूं। सर्वश्रेष्ठ राज्य विजेता बने।'

वस्तुओं पर बाजार शुल्क युक्तिसंगत बनाने के लिए एक समिति गठित की जाएगी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य में वस्तुओं पर बाजार शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके सुचारू व्यवसाय के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 16वीं से 7वीं रैंक तक सुधार हुआ है। जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर जीएसटी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कार्यालयों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि संकट के समय में व्यापारियों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की मांग पर भी राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों को समूह बीमा योजना के तहत लाने के मामले पर भी विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में अनुपालन संबंधी प्रश्नों और हितधारकों के मुद्दों के समयबद्ध निवारण के लिए और जीएसटी कानून और प्रक्रियाओं में हो रहे परिवर्तनों के बारे में अवगत कराने के लिए टैक्स हाट कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग जीएसटी राजस्व वृद्धि के लिए स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी अप्रासंगिक नियमों को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि व्यापारियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि दुकानों से सैंपल लेने वाले स्वास्थ्य अधिकारी या कोई भी सरकारी प्राधिकारी इस संबंध में व्यापारियों को तुरंत भुगतान करें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय को भी युक्तिसंगत बनायेगी ताकि व्यापारियों के हित सुरक्षित रखते हुए उन्हें सुविधा प्रदान की जा सके।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा ने व्यापारिक समुदाय की मांगों पर ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को राज्य में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय व्यापारी सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के कुटलेहड़ और हरोली विधानसभा क्षेत्रों के लिए 67 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऊना जिले के अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान जिले के कुटलेहड़ और हरोली विधानसभा क्षेत्रों

के लिए लगभग 67 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने समूर कलां में 16.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कला केंद्र ऊना का लोकार्पण किया। उसके उपरांत, उन्होंने थानाकलां में हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड मंडल, बंगाणा में ग्रामीण विकास मंडल, बसाल में कृषि विभाग का एसएमएस कार्यालय, टयूरी बडोली और कियारियां में पटवार वृत्त, बीहरू में फील्ड कानूनगो कार्यालय खोलने, हरोट, चारड़ा, बल्ह खालसा और बोहरू में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने चुलहरी, चमियारी और धमांदरी में पशु औषधालय को पशु चिकित्सालयों में स्तरोन्यन, प्राथमिक विद्यालय टीहरा और काकराना का माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्यन, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नारी का उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय टियूराई को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर बंगाणा में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी का एक पद सृजित करने की भी घोषणा की।

उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धमांदरी एवं रैंसरी में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समूर कलां में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र हि नाबार्ड के अन्तर्गत जिले की तीन प्रमुख सड़कों के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ऊना जिला पिछले चार वर्षो में चहुंमुखी विकास का गवाह बना है। जिले के विभिन्न भागों में 1600 करोड़ रुपये के विकासात्मक कार्यो को समर्पित व पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कला केन्द्र निश्चित रूप से क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य ने सुनिश्चित किया कि विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे। इस कठिन दौर में बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी स्तरों पर मजबूती प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता हताशा में बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के अन्तर्गत पांच लाख से अधिक परिवारों को पंजीकृत किया गया है और अब तक राज्य के 2.17 लाख लोगों के उपचार पर 200 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निरंतर देखभाल के लिए 3000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना ने हिमाचल प्रदेश को देश का पहला धुआंमुक्त राज्य बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गौ सदनों में रखी गई प्रति गाय पर प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है

मुख्यमंत्री ने 14.70 करोड़ रुपये से बनने वाले 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल, बंगाणा का शिलान्यास किया। उन्होंने 15.54 करोड़ रुपये से उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना धार चामुखा, पीपलू, धरोह सरोह तथा चमियारी सिहाना के संवर्द्धन कार्य तथा नलूट के लठयाणी में 5.47 करोड़ रुपये की 33/11 के.वी, 1X3.15 एमवीए उप-केन्द्र जिसमें चार आउटगोइंग फीडर्स, नियंत्रण कक्ष भवन तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बंगाणा के विद्युत उप-मण्डल के तहत कर्मचारी भवन की आधारशिलाएं रखीं।

मुख्यमंत्री ने अन्दरोली गांव में नई राहें-नई मंजिलें के तहत 2.60 करोड़ रुपये से बनने वाले जलक्रीड़ा भवन तथा थानाकलां में 3.73 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के ओ.पी.डी. खण्ड की भी आधारशिला रखीं।

इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने ऊना के बाबा बाल आश्रम का दौरा किया।

इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने 3.82 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस विभाग के नवनिर्मित प्रशासनिक खण्ड तथा हरोली के झलेड़ा में 3.95 करोड़ रुपये से निर्मित आर.टी.पी.सी.आर. लैब पालकवाह का लोकार्पण किया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि गत चार वर्षो के दौरान कुटलैहड़ क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की पानी की समस्या का निवारण सुनिश्चित हुआ है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व को जाता है। उन्होंने कुटलैहड़ क्षेत्र के लोगों के हितों की अनदेखी के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार की निन्दा की। उन्होंने क्षेत्र में 67 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि थानाकलां में 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले गोकुलग्राम का कार्य शीघ्र पूर्ण होने जा रहा है तथा समूर में 10.22 करोड़ रुपये की लागत से चौक डैम निर्मित किया जा चुका है। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों की भी विस्तृत जानकारी दी।

जिला भाजपाध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का इस अवसर पर स्वागत किया। छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती, विधायक बलबीर सिंह व राजेश ठाकुर, सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश में पार्टी का सदस्यता अभियान 31 मार्च तक पूरा करना होगा:दासमुंशी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सगंठनात्मक चुनावों की पीआरओ पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दासमुंशी ने कहा है कि प्रदेश में पार्टी का सदस्यता अभियान 31 मार्च तक पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि देश मे कांग्रेस सगंठनात्मक चुनावों के लिये सदस्यता अभियान का तय सीमा में पूरा होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके पूरा होने से कांग्रेस को ओर मजबूती मिलेगी।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए दासमुंशी ने कहा कि वह जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों व ब्लाकों का दौरा कर पार्टी सदस्यता अभियान का जायजा लेंगी और पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त आम लोगों से इस बारे बातचीत करेगी। दासमुंशी ने कहा कि कांग्रेस ऑनलाइन सदस्यता अभियान भी शुरू कर रही है जिससे कांग्रेस के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों विशेष तौर पर सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को जोड़ा जा सकें।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पीआरओ दीपा दासमुंशी व एपीआरओ शमीमा रैना का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार उप चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत व एकजुटता का संदेश पूरे देश मे गया है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान पर वह स्वम् अपनी नज़र रखें हुए है।

राठौर ने कहा कि प्रदेश में सदस्यता अभियान 19 नवम्बर से देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती से प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला की उपस्थिति में शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना व मौसम की बेरुखी के चलते सदस्यता अभियान की गति में कुछ कमी आई है पर उन्हें उम्मीद है कि यह कार्य तय सीमा में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य की उचित देखरेख के लिए जिला स्तर पर महासचिव समन्वयक नियुक्त किये गए है।

राठौर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान 10 सालों के लबे अंतराल के बाद हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार कांग्रेस के सदस्य लक्ष्य से अधिक बनेंगे।

कांग्रेस महासचिव सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी चेतराम ठाकुर ने सदस्यता अभियान के कार्य प्रगति की पूरी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पांच लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में सभी 13 सगंठनात्मक जिलों के अध्यक्षों ने अपने अपने जिलों में सदस्यता अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता कुलदीप पठानिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन पूरी तरह मजबूत है। इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी, एनएसयूआई के अध्यक्ष छत्र सिंह, सेवादल के मुख्य सगंठक अनुराग शर्मा व महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भी बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर अपने अपने विचार रखे।

एसजेवीएन ने 66 मेगावाट की धौलासिद्ध परियोजना के इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्यों के लिए अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए

शिमला/शैल। एसजेवीएन ने मैसर्स वोइथ हाइड्रो (प्रा.) लिमिटेड के साथ हिमाचल प्रदेश में 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल संकार्यो के लिए एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए।

नन्द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में एसजेवीएन के मुख्य महाप्रबंधक (ईसीडी) एस.के. सूद तथा मैसर्स वोइथ के उपाध्यक्ष, राज विद्यार्थी द्वारा अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर गीता कपूर निदेशक (कार्मिक), एस.पी.बंसल, निदेशक (सिविल), अखिलेश्वर सिंह, निदेशक (वित्त), सुशील शर्मा, निदेशक (विद्युत), संजीव कुमार, सीएफओ (मैसर्स वोइथ हाइड्रो (प्रा.) लिमिटेड) तथा एसजेवीएन एवं मैसर्स वोइथ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

नन्द लाल शर्मा ने अवगत कराया कि 136.64 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रो-मेकेनिकल संकार्यो को मैसर्स वोइथ हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड किया गया हैं। परियोजना के सिविल तथा हाइड्रो-मैकेनिकल संकार्यो को पहले ही दिनांक 06 मई 2021 को अवार्ड कर दिया गया है। विभिन्न सिविल घटकों पर निर्माण गतिविधियां तीव्र गति से चल रही हैं।

शर्मा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना की आधारशिला दिनांक 27 दिसंबर, 2021 को रखी थी। भारत सरकार ने पहले ही 687.97 करोड़ रुपए की परियोजना लागत को मंजूर प्रदान की तथा इस परियोजना के लिए 21.6 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी प्रदान की है। परियोजना को मई 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

शर्मा ने जानकारी दी कि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ, धौलासिद्ध एचईपी के लिए इलेक्ट्रो मैकेनिकल घटकों के निर्माण का कार्य आरंभ हो जाएगा। इससे परियोजना की गतिविधियों में तेजी लाने और परियोजना को समय से पहले पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी।

परियोजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताते हुए शर्मा ने कहा कि इस परियोजना में 70 मी. ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी स्टोरेज बांध का निर्माण शामिल है। डैम टो सरफेस विद्युत गृह में वर्टिकल फ्रांसिस टरबाईन के साथ 33 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाईयां स्थापित की जाएगी। परियोजना से 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में 304 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन होगा। परियोजना के पूरा होने पर पर्यावरण में वार्षिक 2.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 8 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा।

वर्तमान में, एसजेवीएन के पास 16400 मेगावाट से अधिक का पोर्टफोलियो है तथा यह भारत, नेपाल एवं भूटान में जलविद्युत, ताप तथा सौर विद्युत में विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। कंपनी ने विद्युत पारेषण एवं पावर ट्रेडिंग के अन्य क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। एसजेवीएन वर्ष 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 25000 मेगावाट तथा वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है।

अनियमितताओं के चलते दो फर्मों के लाइसेंस निलंबित

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित दो फर्मो द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाये जाने के कारण दो फर्मो के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त फर्मो द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा था जिसके तहत उपरोक्त फर्मो के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

आबकारी आयुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त, विभाग ने जिला हमीरपुर में दो लाइसेंसियों की अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनकी हमीरपुर स्थित 13 दुकानों को सील कर उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। वहीं जिला कांगड़ा में भी निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध शराब मिलने पर लाईसेंसी की दुकान को सील किया गया है। इस संदर्भ में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कार्रवाई जारी रखेगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

प्रदेश किसान यूनियन ने जयराम सरकार को भेजा मांग पत्र

- केंद्रीय बजट से निराश होकर राज्य सरकार से अपने बजट में इन्हें पूरा करने को कहा
- देश के जीडीपी का 45% किसानी बागवानी से आता है
- रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर भी यही क्षेत्र पैदा करता है

शिमला/शैल। किसान की राजनीतिक ताकत कितनी और क्या है इसका एहसास तेरह माह चले किसान आंदोलन ने सबको करवा दिया है। इसी आंदोलन के कारण अंततः सरकार को विवादित कृषि कानून वापस लेने पड़े। किसानों के खिलाफ बनाये गये आपराधिक मामले वापस लेने और एम एस पी के लिये कमेटी गठित करने की घोषणायें करनी पड़ी। संसद में जब कृषि कानून वापस लेने का बिल पारित हो गया तो उसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन व्यवहारिक रुप से जब मामले वापस लेने और एम एस पी के लिये कमेटी गठित करने की घोषणाओं पर अमल नहीं हो सका तब किसान यूनियन ने फिर से आंदोलन की घोषणा कर दी है। 2023 में भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किसान नेताओं की ओर से आ गया है। इसके लिए किसान संगठन ने जो रणनीति अपनाई है उसके तहत एक पूरे शोध के बाद कुछ किसान समस्याओं को चिन्हित करने के बाद इन्हें राज्य सरकारों को भेजा गया है। हिमाचल में भी भारतीय किसान यूनियन ने इसके अध्यक्ष अनेंदर सिंह नॉटी की अध्यक्षता में राज्य सरकार को एक ग्यारह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार के बजट से किसानों को घोर निराशा हुई है। इसलिए राज्य सरकार से मांग की गई है कि वह अपने बजट में किसानों की इन मांगों को पूरा करने के लिए निश्चित और ठोस कदम उठाये। इस मांग पत्र में साफ कहा गया है कि प्रदेश की 80% जनता कृषि और बागवानी पर आश्रित है रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर भी यही क्षेत्र पैदा करता है। मांग पत्र में यह भी साफ कर दिया गया है कि सरकार जिस गंभीरता से प्रदेश के कर्मचारियों वर्ग को लेती है किसानों को उससे भी ज्यादा गंभीरता से लें। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि क्या जयराम सरकार अपने बजट में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए व्यवहारिक कदम उठा पाती है या नहीं।

यह है किसानों का मांग पत्र

1. केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने में पूर्णत विफल रही है इसलिए स्थानीय परिस्थितियों और मौसम को देखते हुए राज्य सरकार अपने स्तर पर फसल बीमा योजना लाए ताकि हिमाचल के किसानों को इसका असली लाभ मिल सके।

2. हिमाचल प्रदेश के किसानों, बागवानों, खासतौर पर ऊपरी क्षेत्र के बागवानों हेतु यूटिलिटी तथा पिकअप जैसे वाहन जो अभी तक 'व्यवसायिक श्रेणी' में रखे गये हैं उनको 'प्राइवेट रजिस्ट्रेशन' के दायरे में लाया जाये तथा इस पर भी 'ट्रैक्टर' की तर्ज पर सरकार सब्सिडी दे क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैक्टर से अधिक इन वाहन की जरूरत पड़ती है तथा खेती में उपयोग होने वाली वस्तुओं से लेकर अपनी फसल की ढुलाई के लिए इन वाहनों की सारा साल जरूरत पड़ती है। निजी उपयोग के बावजूद व्यवसायिक श्रेणी में होने के कारण किसानों को 'रोड टैक्स, पासिंग और इंश्योरेंस' के रूप में भारी-भरकम पैसा सरकार को भरना पड़ता है।

3. कृषि उपज मंडी समिति की आय का खर्च भी किसानों के लिए होना चाहिए और किसी अन्य मद में इसका पैसा खर्च ना हो। एपीएमसी की आय का एक हिस्सा 'कोल्ड स्टोर बनाने और खेती में रिसर्च' हेतु रखा जाए। हिमाचल प्रदेश में हर ब्ल क स्तर पर एक नई मंडी बनाई जाए तथा पहले से मौजूद मंडियों की क्षमता और सुविधा बढ़ाई जाए। टमाटर, अदरक, लहसुन, सेब, स्टोन फ्रूट पर आधारित पल्प प्लांट्स को लगाया और बढ़ावा दिया जाए फल सब्जी साथ मटर आदि के कैनिंग यूनिट भी कृषि मंडी में लगाए जाएं।

4. पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सड़क नहीं है वहां फसलों को सड़क तक लाने हेतु छोटे रोपवे पर भी सरकार 80% तक सब्सिडी का प्रावधान करें इससे सुदूर पहाड़ों पर बगीचों में नए होमस्टे भी खुलेंगे तथा किसान पर्यटन के द्वारा भी अपनी आर्थिकी को मजबूत कर पाएंगे।

5. गेहूं के साथ मक्की हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है, इसलिए सरकार 2022 वर्ष से मक्की की फसल की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद सुनिश्चित करे तथा हिमाचल प्रदेश की मक्की का आटा पूरे भारत में सबसे अधिक पौष्टिक तथा गुणवत्ता वाला है इसलिए सरकारी डिपो में गेहूं के साथ-साथ मक्की का आटा भी उपलब्ध करवाया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश में खरीदी गई 'मक्की का आटा हिमाचल प्रदेश में ही रसोई घरों' तक पहुंचे।

6. हिमाचल प्रदेश में किसानों की सुविधा तथा फसलों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर चेन के लिए उचित बजट का प्रावधान हो तथा हिमाचल प्रदेश में 'कोल्ड स्टोर कॉरपोरेशन' की स्थापना करके अलग से विभाग बनाया जाए।

7. भांग व अफीम के औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए सरकार इसकी खेती को कानूनी दर्जा जल्द से जल्द प्रदान करें।

8. इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में धान की खरीद में किसानों को बहुत दिक्कत आई जिसका मुख्य कारण किसी प्रादेशिक एजेंसी का मध्यस्थ ना होना रहा है अतः सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन व कृषि उपज मंडी समिति को खरीद में मध्यस्थ नियुक्त किया जाए तथा टोकन की व्यवस्था को और सरल किया जाए।

9. जिला सिरमौर स्थित धौलकुआं में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हो ताकि किसानों के बच्चे कृषि के विषय में पढ़ाई कर सकें। इसके अतिरिक्त स्कूली पाठयक्रम में भी कृषि बागवानी को दसवीं तक पाठयक्रम में शामिल किया जाए।

10. बड़े शहरों में किसान हाट हेतु जगह उपलब्ध करवाई जाए जहां किसान अपने उत्पाद सीधे बेच पाए और उपभोक्ता को भी ताजे फल सब्जी सीधे सस्ते मिलें।

11. दिल्ली चंडीगढ़ देहरादून जैसे शहरों हिमाचल के फलों और सब्जी के अपने आउटलेट हों और हिमाचली ब्रांड के तहत सीधे किसानों से खरीद कर कृषि विभाग वहां फल सब्जी बेचे।

पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ

शिमला/शैल। टौणीदेवी सिविल अस्पताल से मरीजों के इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर सुविधा (रेफर हुए मरीजों) को बड़े हस्पताल, टांडा

मेडिकल कॉलेज एवं हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए साँसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की एम्बुलेंस अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करेंगी।

अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल, के मार्गदर्शन में प्रयास संस्था के सहयोग से संचालित मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करते हुए अब सुजानपुर सिविल अस्पताल के बाद, टौणीदेवी सिविल अस्पताल से भी रैफर हुए मरीजों को नजदीकी उच्च स्तरीय अस्पताल में ले जाने के लिए नई एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा एम्बुलेंस की चाबी बी. एम.ओ. टौणीदेवी को सौंप कर किया गया। इस एम्बुलेंस के लिए चालक, इसके रखरखाव की देखरेख प्रयास संस्था ही करेंगे एवं सभी खर्चे भी संस्था द्वारा ही वहन किए जाएंगे। एक ऐसी ही एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ सुजानपुर सिविल अस्पताल से किया गया था एवं एक अन्य एम्बुलेंस AIIMS बिलासपुर से मरीजों को लाने ले जाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है ।

प्रयास संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी चार संसदीय क्षेत्रों के प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में 'अस्पताल-जनता- के-घर-द्वार' मुहिम के तहत 30 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, रक्त जांच, एवं दवाइयों का वितरण कर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। कोविड महामारी के दौरान भी केंद्रीय मंत्री के सहयोग से इन एम्बुलेंस सेवाओं के द्वारा जनता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। ऑक्सिजन सिलेण्डर, मास्क, सैनिटाइजर जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा द्वारा जनहित में किया जा रहा।

किसके नेतृत्व में

.....पृष्ठ 1 का शेष

बतौर नेता प्रतिपक्ष जिस कदर मुकेश अग्निहोत्री जयराम और उनकी सरकार पर आक्रामक रहे हैं उसके कारण वह आज मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के हर छोटे बड़े नेता के निशाने पर चल रहे हैं। जब विधानसभा में राज्यपाल से ही टकराव की स्थिति धरने प्रदर्शन तक पहुंच गई थी तब संगठन की ओर से कोई बड़ा योगदान नहीं मिल पाया है यह कई दिन चर्चा का विषय बना रहा था। आज भी सदन के भीतर जो आक्रमकता कांग्रेस की सामने आती है उसके मुकाबले में संगठन सदन के बाहर कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। अभी तक कांग्रेस का आरोप पत्र सामने नहीं आ पाया है। जबकि भाजपा ने हर चुनाव में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर आरोप लगाये हैं। स्व.वीरभद्र सिंह के खिलाफ बने मामलों को प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के हर नेता ने हर चुनाव में उछाला है। यह अब एक चुनावी संस्कृति बन गयी है कि जब तक विरोधी को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं घेरा जायेगा तब तक जनता आपको गंभीरता से नहीं लेती हैं। प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व अभी तक मुख्यमंत्री जयराम और उनके दूसरे सहयोगियों को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं घेर पाया है। जबकि दर्जनों गंभीर मामले सामने हैं। अभी घटे शराब कांड में ही भाजपा के दो बड़े नेताओं के नाम हर आदमी की जुबान पर हैं। लेकिन कांग्रेस नेता यह नाम लेने से बच रहे हैं। आज शायद प्रदेश के सात-आठ ठेकेदारों के पास ही सात सौ करोड़ से अधिक के ठेके हैं। एक मंत्री का भाई तो शायद पूरे जिले को संभाल रहा है। जनता में यह चर्चायें आम है लेकिन कांग्रेस मौन है। कांग्रेस का यह मौन तोड़ने के लिए हाईकमान को समय रहते नेतृत्व के सवालों को सुलझा लेना होगा अन्यथा नुकसान हो सकता है। जातीय समीकरण भी प्रभावी रहते हैं इस पर अगले अंक में चर्चा की जायेगी।